

अपने ही प्रतिष्ठानों से उत्पीर्ण हुए शिक्षुओं को प्राथमिकता देते हैं। तथापि शिक्षुओं के प्रशिक्षण को रोषगार अचसरीं के अनुकूल बनाने की दृष्टि से सरकार का शिक्षुओं के प्रशिक्षण की योजना का पुनरीक्षण करने का प्रस्ताव है।

अंशमान तथा निकोबार में खनिजों की खोज

5961. श्री राम जीवन सिंह : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) अंशमान तथा निकोबार द्वीप-समूह में खनिज संसाधनों की खोज तथा विकास के बारे में सरकार के क्या प्रस्ताव हैं; और

(ख) क्या लक्षद्वीप में भी खनिज संसाधनों की खोज करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुन्डा) : (क) भारतीय भू-बैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा अंशमान और निकोबार द्वीप समूह में खनिजों की खोज जारी है और वर्तमान क्षेत्रगत सर्वे (1977-78) के कार्यक्रम में प्लेटिनम, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम आदि के लिए भूद्रुमैतिक चट्टानों का सर्वेक्षण, जलज मिट्टी की खोज तथा तांबा खनिजीकरण के लिए समेकित खोज शामिल हैं। ये खोज कार्य अभी प्रारम्भिक अवस्था में हैं और जब तक खोज का काम पूरा नहीं हो जाता तथा निक्षेपों की प्राथमिक उपादेयता की पुष्टि नहीं हो जाती तब तक इन खनिजों के सम्पयोजन के बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी।

(ख) भारतीय भू-बैज्ञानिक सर्वेक्षण ने लक्षद्वीप के सभी बड़े सम्पदाओं में समन्वेषण किया है जिसके फलस्वरूप एक मीटर की गहराई पर चूनेदार मिट्टी के लगभग 2880 लाख टन अंशार होने का अनुमान लगाया गया है।

डायल बुमाकर सीछे टेलीफोन करने की सुविधा प्राप्त उत्तर प्रदेश के नगर

5962. श्री गंगा प्रवल सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के उन नगरों के क्या नाम हैं जहाँ पर सरकार का विचार वर्ष 1978-79 में डायल बुमाकर सीछे टेलीफोन करने की सुविधा उपलब्ध कराने का है; और

(ख) लखनऊ से कितने जिला मुख्यालयों को जोड़ दिया गया है तथा और कितने जिलों को जोड़ दिये जाने की आशा है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद मुखर्जी साय) : (क) गोरखपुर और सीतापुर।

(ख) पाच जिला मुख्यालयों अर्थात् इलाहाबाद, फैजाबाद, कानपुर, उन्नाव, और वाराणसी को उपभोक्ता टुक डायलिंग सेवा के जरिये लखनऊ से जोड़ा जा चुका है। आशा है कि चार और जिला मुख्यालयों अर्थात् भागरा, गोरखपुर, रायबरेली और सीतापुर को वर्ष 1978-79 के दौरान लखनऊ से जोड़ दिया जाएगा।

ग्रामों में तारों का वितरण

5963. श्री गंगा प्रवल सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में तारों के वितरण में सामान्य तलों के वितरण से अधिक समय लगता है ;

(ख) यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) तारों के महत्व को देखते हुए सरकार ने उन्हें शीघ्र वितरित कराने के लिये या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मरहरि प्रसाद मुखर्जी साय) : (क) जी नहीं :

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) (i) जब कोई तार पाने वाला व्यक्ति किसी तारघर के मुक्त वितरण क्षेत्र के बाहर रहता है, और यदि तार भेजने वाले ने उस तार की डिलीवरी विशेष सदेशवाहक के जरिए करने के लिए दुलाई शुल्क भ्रदा न किया हो, तब वह तार (भारतीय तार नियम 84 के अनुसार) पाने वाले के पास डाक से भेज दिया जाता है ।

तारों का इस प्रकार निपटारा कम से कम किया जाए, इस के लिए देहाती इलाकों में अधिक से अधिक तारघर खोले जा रहे हैं ।

(ii) जहाँ कहीं यातायात की दृष्टि से श्रीचित्त सख होता है, मार्ग में लगने वाला समय कम करने के लिए सीधे मार्गों की व्यवस्था की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश में काटे गये टैलीफोन कनेक्शनों को बहाल किया जाना

5964. श्री गंगा भक्त सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान राजनीतिक कारणों से काटे गये टैलीफोन कनेक्शनों को अब तक बलहा नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हा, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उत्तर प्रदेश में ऐसे टैलीफोन कनेक्शनों की संख्या क्या है जिन्हें अभी बहाल किया जाना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मरहरि प्रसाद मुखर्जी साय) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश में केवल एक टैलीफोन

कनेक्शन को छोड़ कर बाकी सभी टैलीफोन कनेक्शन दुबारा चालू कर दिए गए हैं । संबंधित पार्टी उपलब्ध नहीं है ।

दिल्ली में ईंट के भट्टों में काम कर रहे बन्धुघा श्रमिक

5965. श्री श्रीम प्रकाश त्यागी : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली और इसके आस-पास 350 ईंट के भट्टों में लगभग 50,000 श्रमिक बन्धुघा श्रमिकों के रूप में कार्य कर रहे हैं ,

(ख) क्या सरकार ने इस तथ्य की जांच कर ली है, और

(ग) यदि हा, तो उसका ब्यौरा क्या है और उन्हें मुक्त कराने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : (क) से (ग). दिल्ली प्रशासन ने, जिसका ध्यान इस मामले की ओर दिलाया गया था, सूचित किया है कि उनकी सूचना के अनुसार दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में बधित श्रमिकों का कोई मामला नहीं है और न ही बधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के उपबधों के उल्लंघन की कोई सूचना मिली है ।

Visit of Vice-President of Korea

5966. SHRI G. M BANATWALLA;
SHRI MUKHTIAR SINGH
MALIK;

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Vice-President of Democratic People's Republic of Korea